**Corruption in Railways**

338. DR. BAPU KALDATE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the report appearing in the 'Tribune' dated the 1st January, 1996, regarding corruption in the higher ranks of the Indian Railways in collusion with the Food Corporation of India and Government procuring agencies in the allotment of rakes for transportation of foodgrains; and

(b) if so, what action has been taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SURESH KALMADI): (a) Yes, Sir. However, neither any complaint nor any corrupt practice of such nature has come to the notice and the newspaper report was not found correct.

(b) Doss not arise.

**Killings in J & K**

339. SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of civilians and paramilitary personnel killed/injured due to Pakistani firing and subversive activities during December, 1995 and January, 1996 and in February, 1996, separately category-wise and month-wise;

(b) whether any compensation has been paid to the civilians;

(c) if so, the details thereof; and

(d) what preventive steps have been taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): (a) As per available information only one civilian died due to Pakistani firing on the Jammu border during the month of January, 1996. The details regarding civilians and security force personnel who were killed/injured due to subversive activities during the period are as under:—

| | | December 1995 | January 1996 | February, 15, 1996 |
|---|---|---|---|---|
| Civilians | Killed | 82 | 105 | 71 |
| | injured | 67 | 74 | 39 |
| S/forces | Killed | 05 | 12 | 04 |
| | injured | 16 | 26 | 13 |

(b) and (c) An ex-gratia relief of Rupees one lakh in each case in being paid to next of kin of the innocent civilians killed in Pakistani firing and militant violence in the state.

(d) Various steps have been taken to contain incidence of border/LOC firing and to fight militancy in the state, which inter alia include flag meetings between field commanders, intensified patrolling along the LOC, coordination between security forces, and setting up of village defence committees.

**Indo-US joint military exercise**

340. SHRI E. BALANANDAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a joint military exercise between India and the US is going to be held shortly in the Arabian sea; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DEPARTMENT OF DEFENCE AND

THE DEPTT. OF DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT) (SHRI MALLIKARJUN): (a) and (b) A proposal is currently under consideration of the Government for a joint military exercise between the Indian and US Navies. A decision has not yet been taken.

### भारत में कम्प्यूटर विकास

341. **श्री अजीत जोगी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम्प्यूटर विकास के क्षेत्र में भारत अन्य देशों में इसकी औसत दर की तुलना में पिछड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में सूचना प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे के विकास हेतु कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलिरियो):** (क) और (ख) भारत में प्रति एक हजार व्यक्ति पर कम्प्यूटरों की संख्या 0.7 है जबकि इसकी तुलना में विश्व का औसत 25 है। इसका कारण यह है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रसार अभी तक व्यापक रूप से नहीं किया गया है। किन्तु भारत में कम्प्यूटर के विकास में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस समय भारत में कम्प्यूटर के विकास की औसत वृद्धि दर 23% दर है जबकि विश्व में औसत वृद्धि दर 7% है।

(ग) और (घ) सरकार ने देश में सूचना प्रौद्योगिकी की मूल संरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए पहल किए है। कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास के लिए अनुसंधान तथा विकास संबंधी कार्य करने के लिए उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक) पुणे, इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र (ईआरएण्डडीसी) और इलेक्ट्रानिक डिजाइन तथा परीक्षण केन्द्र में सुविधाएं स्थापित की गई है। ये केन्द्र मुख्यतः समानांतर अभिकलन, प्रतिबिम्ब संसाधक तथा साफ्टवेयर विकास के क्षेत्र में कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास तथा उसका दर्जा बढ़ाने के लिए अनुसंधान तथा विकास के कार्य कर रहे हैं।

इलेक्ट्रानिकी विभाग ने साफ्टवेयर निर्यात के लिए मूल संरचनात्मक सुविधाओं के विकास की कई परियोजनाओं को कार्यान्वित किया है। इलेक्ट्रानिकी विभाग ने पुणे, हैदराबाद, बंगलौर, गांधीनगर, नोएडा, भुवनेश्वर तथा त्रिवेन्द्रम में साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) स्थापित किए हैं।

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र ने पूरे देश में कम्प्यूटरीकरण तथा नेटवर्किंग उपलब्ध कराने की सुविधा स्थापित की है। इलेक्ट्रानिकी विभाग भी सरकारी विभागों में कम्प्यूटरीकरण को बढ़ावा दे रहा है। आरम्भ की गई परियोजनाओं में आयकर विभाग सीमाशुल्क, पुलिस विभाग, भारतीय मानक ब्यूरो आदि का कम्प्यूटरीकरण शामिल है।

इलेक्ट्रानिक मेल बुलेटिन बोर्ड जैसे व्यापक रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले अनुपयोगों तथा वर्ल्डवाइड वेब (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू) जैसे इन्टरनेट अनुप्रयोगों को इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित शिक्षा तथा अनुसंधान नेटवर्क (अर्नेट) नामक नेटवर्क पर उपलब्ध कराया जा रहा है। आई-नेट, आरएबीएमएन जैसे सार्वजनिक विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क (वैन) दूरसंचार विभाग द्वारा कार्यान्वित किए गए हैं। वैन पर आधारित अनुप्रयोगों के लिए वीसैट रप आधारित नेटवर्क भी कार्यान्वित किए गए हैं।

इनके अतिरिक्त, भारतीय भाषाओं में सूचना संसाधन साधनों का विकास करने के उद्देश्य से सरकार ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी विकास नामक कार्यक्रम आरम्भ किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने गए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निम्नलिखत शामिल हैं:—

1. भारतीय भाषाओं के मूल-पाठ के शब्द-संग्रह का विकास

2. मशीन साधित अनुवाद प्रणाली

3. प्राकृतिक भाषा संसाधन के मूलतत्व

4. कम्प्यूटर साधित अध्ययन एवं अध्यापन पैकेजों का विकास

सरकार ने आभासी वास्तविकता, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पहल की है जिनके विकास की प्रचुर संभावनाएं है। देश में आभासी वास्तविकता प्रौद्योगिकी के बारे में